

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र.
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्र. सूअप्र/संतशि/2019/275

भोपाल, दिनांक/09/07/2019

प्रति,

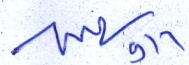
✓
प्राचार्य/लोक सूचना अधिकारी,
समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थाएँ,
मध्यप्रदेश।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-05 का पालन किये जाने के संबंध में ।
—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1411/1433/2019/42-2, दिनांक 28.6.2019 के साथ म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-90/2019/सूअप्र/1-9/479, दिनांक 21.6.2019 संलग्न प्राप्त हुई है (छायाप्रति संलग्न)। शासन द्वारा श्री वरुण नामदेव जिला-उमरिया द्वारा माननीय मुख्य सूचना आयुक्त को संबोधित ज्ञापन दिनांक 13.2.2019 की छायाप्रति संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त बिन्दुओं का पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त ज्ञापन के बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

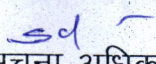
संलग्न :- उपरोक्तानुसार


लोक सूचना अधिकारी
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
भोपाल - मध्यप्रदेश

पृ0क्र. सूअप्र/संतशि/2019/
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक/ /07/2019

1. उप सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की ओर ज्ञाप क्रमांक 1411/1433/2019/42/2, दिनांक 28.6.2019 के संबंध में सूचनार्थ।
2. प्रमुख आइटीआई अधिकारी, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल की ओर उपरोक्त परिपत्र वेब पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु अग्रेषित।


लोक सूचना अधिकारी
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
भोपाल - मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

—:000:—

क्रमांक 1411 / 1433 / 2019 / 42 / 2
प्रति,

भोपाल दिनांक 28 / 06 / 2019

1. संचालक
कौशल विकास संचालनालय
जबलपुर, म0प्र0।
- ✓ 2. संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
म0प्र0भोपाल।
3. आयुक्त,
रोजगार संचालनालय,
विंध्याचल भवन, भोपाल।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पालन किए जाने के संबंध में।

—:000:—

उपरोक्त विषय में लेख है कि उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 21.06.2019 का अवलोकन करें। जिसमें श्री वरुण नामदेव जिला - उमरिया द्वारा माननीय मुख्य सूचना आयुक्त को संबोधित ज्ञापन दिनांक 13.02.2019 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त ज्ञापन के बिन्दुओं का पालन करने हेतु निर्देशित किया है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(पंकज शर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

3
28/6
J.D. XI

UH 28/6

का. (10)
25/6/19



मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
सूचना का अधिकार विभाग
पत्र क्र. 1433
दिनांक 26/06/2019

क. एफ 11-90/2019/सूअप्र/1-9/439
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/06/2019

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का पालन किए जाने के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश सूचना आयोग, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक क्यू/रासूआ/उमरिया/2019/7602, दिनांक 10.05.2019 के साथ आवेदक श्री वरुण नामदेव, जिला-उमरिया द्वारा मा. मुख्य सूचना आयुक्त को संबोधित ज्ञापन दिनांक 13.02.2019 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त ज्ञापन के बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(धरणेन्द्र कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

पृ.क. एफ 11-90/2019/सूअप्र/1-9/439. भोपाल, दिनांक 21/06/2019
प्रतिलिपी:-

सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की ओर उनके पत्र क्रमांक क्यू/रासूआ/उमरिया/2019/7602, दिनांक 10.05.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)



संजी. क्र. 1138/2019/1-9
दिनांक 13.05.2019

(सीडपोस्ट से)

8

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 website: www.sic.mp.gov.in

क्रमांक-Q/रासूआ/ उमरिया/2019/

7602

भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

✓ मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ,
बल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।

8.01
13/5/19

विषय :

सूचना के अधिकार में पालन एवं संशोधन बाबत।

सन्दर्भ:

जिला उमरिया, म.प्र. के समस्त आरटीआई कार्यकर्ता, द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन
दिनांक 13.02.2019



उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा जिला उमरिया के आरटीआई कार्यकर्ता श्री वरुण नामदेव द्वारा ज्ञापन दिनांक 13.02.2019 आयोग को प्रेषित किया गया है, जिसमें मा0 मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये आदेशानुसार बिन्दु क्रमांक 01 से 09 आपके कार्यालय से संबंधित है। अतः आवेदन की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

(मा. मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशानुसार)

संलग्न यथोपरि।

(पराग करकरे)

अवर सचिव

राज्य सूचना आयोग

श्रीमान् मुख्य सूचना आयुक्त महोदय

राज्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग 36 बी, अरेरा हिल्स सोपान (मोप्र)

विषय:- सूचना के अधिकार में पालन एवं संशोधन बाबत

महोदय,

निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 (6) (1) के प्रावधानों के तहत सरकार के आधीन शासकीय कार्यालयों में सूचना के अधिकार अधिनियम के पत्रों का निराकरण नहीं किया जाता। प्रार्थी का भी कई सम्भावनाओं पर पत्रों की जानकारी नहीं है। प्राचीन विचारों अनावश्यक प्रार्थी को परेशानी अलग पड़ती है।

1. यह कि शासन के नियमानुसार शासकीय विभागों एवं वित्त पोषित संस्था जिन जिन विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है उन सभी विभागों एवं वित्त पोषित संस्था में सूचना का अधिकार संबंधित नियम कार्यालय में नहीं लिखे होने से आम लोगों का परेशानी होती है, जिसे लिखा जाये।
2. यह कि अधिकतर विभागों में अपीलीय अधिकारी का नाम व पता, संपर्क नंबर अंकित नहीं है जिसे अंकित कराया जाये।
3. यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी जिले के कलेक्टर को बनाया जाये, क्योंकि तत्पुस्त संचालक संभागीय अधिकारी को बनाने से अपीलार्थी का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं अन्य परेशानियां होती है।
4. यह कि जमानों में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु सूचना पटल पर लोक सेवावेज जो सूचना का अधिकार नियमानुसार शासकीय विभागों में अपीलार्थी को सूचना का अधिकार आवेदन करने पर दिये जा सकते हैं, जिसे आम जन की जानकारी हेतु प्रदर्शित की जाये।
5. यह कि शासकीय विभाग में एक कर्मचारी को इसी कार्य के लिए प्रदत्त किया जाये जो समय पर सूचना का अधिकार आवेदन का जानकारी दे। इससे शासकीय कार्य प्रभावित न हो सके।
6. यह कि अपीलार्थी को प्रथम व द्वितीय अपील उत्पत्ती उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों पर सुना जाये, क्योंकि अपीलार्थी को आर्थिक शारीरिक मानसिक व समय अभाव के कारण वह नहीं पहुँच पाता। अपीलार्थी के प्रथम या द्वितीय अपील का खर्चा जिस कार्यालय में सूचना का अधिकार का आवेदन किया गया है, उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी से दिलवाया जाये ताकि अपीलार्थी को अनेक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
7. यह कि द्वितीय अपील का निराकरण समय सीमा के भीतर करने की व्यवस्था लागू की जाये, कई बार देखा जाता है कि वकीलों के आवेदनों पर ही रीढ़ विचार दिया जाता है जिससे दूसरे आवेदक अनावश्यक परेशान होता है। जिससे कानून का सम्मान होता है।
8. यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी पर जानकारी न देने पर जुर्माने का प्रावधान होने के बाद भी प्रथम अपील अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है।
9. यह कि सूचना का अधिकार से संबंधित नियम कार्यालय में चस्था करवाये जायें ताकि आम जनता को सूचना का अधिकार नियम कानून की सही व सटीक जानकारी हो सके।
10. यह कि मोप्र राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलार्थी को पत्र भेजे जाने पर संदर्भित आवेदन से संबंधित पत्र क्रमांक, विभाग का नाम दिनांक को संदर्भित करें। जिससे अपीलार्थी समझ सके कि किस आवेदन का पत्र आया हुआ है।
11. यह कि राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदेश के हर जिलों में शिविर लगाकर अपीलार्थी की द्वितीय अपील का समय सीमा में निराकरण किया जाये।
12. यह कि द्वितीय अपील का निराकरण अपीलार्थी के फोन नंबर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं अन्य सरलीकरण का उपयोग करते हुए निराकरण करवाया जाये जिससे अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम का लाभ असान तरीके से मिल सके।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदन के दिये गए आवेदन के हर बिन्दु पर विचार करते हुए कानून के तहत लोक सेवा में सुधार किया जाये जिससे प्रेरित होकर देश के जन सेवा में सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन करा जाय। इससे अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके।

दिनांक 13-02-2019

स्थान उमरिया जिला उमरिया

समस्त आरटीआई कार्यकर्ता

जिला-उमरिया (मोप्र)

Arjun Nandan